नया ईसीआई-नेट नागरिकों के लिए चुनावी सेवाएं सुगम बनाएगा; चुनाव पदधारियों को डेटा प्रबंधन में आसानी और सुविधा होगी

भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही हितधारकों के लिए एक एकल-बिंदु ऐप लॉन्च करेगा

मौजूदा 40 से अधिक आईटी ऐप्स को इस उन्नत यूआई, यूएक्स वाले ऐप में शामिल किया जाएगा

समर सहारा/प्रेम सैनी/सीकर।

एक प्रमुख पहल के तहत, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचकों और इनके अन्य हितधारकों जैसे चुनाव पदधारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस विकसित कर रहा है। यह नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल बनाएगा। ईसीआई-नेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस (यूआई) और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस (यूएक्स) होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की थी।

ईसीआई-नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में भी सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। संबंधित पदधारी द्वारा की गई प्रविष्टि से यह सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉर्मों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा। ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है (ऐप्स की पूरी सूची संलग्न है)। ईसीआई-नेट से लगभग 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के 10.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 15 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), लगभग 45 लाख मतदान पदधारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ), 4,123 ईआरओ और 767 जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) शामिल हैं। ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुका है और इसकी सुचारू कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों, संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों,संघ राज्य क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करके एक विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ-साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है। ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़े लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।

Data by presiding officers to be final in the event of conflict: ECI

Abhishek Angad

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI :: The Election Commission of India (ECI) on Sunday said that in the event of any "conflict" in voter turnout data, the primary figures filled in statutory forms by booth-level presiding officers will take precedence, with the crucial clarification coming amid growing scrutiny over the accuracy of data shared on poll body's official platforms.

The announcement comes at a time when the ECI is preparing to launch ECINET — a new digital interface for voters, poll officials and political parties which will integrate over 40 of its existing mobile and web applications, including the Voter Turnout App.

According to the poll body, the platform is being developed following an extensive consultative exercise involving 36 chief electoral officers, 767 district election officers, and 4,123 electoral registration officers across states and Union territories. ECINET will allow users to access electoral data on desktops and smartphones, ECI said in a press release on Sunday.

THE POLL BODY'S CLARIFICATION COMES AMID CRITICISM FROM OPPN PARTIES, WHICH ACCUSED ECI OF VOTER DATA MANIPULATION

"To ensure that data is as accurate as possible, the data on ECINET will be entered solely by authorised ECI officials. Entry by the concerned official would ensure that the data made available to stakeholders is as accurate as possible. However, in case of any conflict, the primary data as duly filled in statutory forms will prevail," it added.

The ECI statement effectively means that for voter turnout figures, Form 17C — which records booth-wise voter turnout data filled by presiding officers — will be treated as the final record in case of discrepancies with data displayed on its portal and app.

In addition to the Voter Turnout App, ECINET will also absorb platforms such as the Voter Helpline, cVIGIL (for reporting model code violations), the Affidavit Portal, and others. The initiative aims to benefit nearly one billion eligible voters, 1.05 million booth level officers, 1.5 million booth level agents of political parties, nearly 4.5 million polling officials, and 15,597 assistant electoral registration officers.

The clarification gains significance amid growing criticism from various opposition parties, which accused ECI of voter data manipulation. Last month, senior Congress leader Rahul Gandhi alleged at an event in the that the poll body was "compromised" and that "something is wrong with the system".

निर्वाचन आयोग जल्द लॉन्च करेगा एक बिंदु एप

मौजूदा 40 से अधिक एप की नहीं होगी जरूरत

महानगर संवाददाता

जयपुर। निर्वाचन आयोग विभिन्न अधिकारियों, राजनीतिक दलों और संस्थाओं के सुगम कार्यवहन के लिए एक एप लॉन्च करेगा। इस एप के माध्यम से वर्तमान में वेब और मोबाइल पर उपलब्ध 40 एप को अधिक अनुकूल और एकीकृत बना दिया जाएगा। ईसीआई-नेट में एक यूजर इंटरफेस और एक सरलीकृत यूजर अनुभव होगा, जो चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए एकल प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा। एप के आने पर उपयोगकर्ता को कई एप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। नेवीगेट करने या अलग-अलग लॉगिन याद नहीं रखने होंगे। इससे डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर डेटा उपलब्ध करने में आसानी होगी। इस एप की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मार्च में ही कर ली थी।

पहल **जल्द लॉन्च होगा ईसीआईनेट, 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशन की लेगा जगह**

एक ही एप में अब मिलेंगी चुनाव से जुड़ी सभी सुविधाएं

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग देशभर के करोड़ों मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक ऐसा एप विकसित कर रहा है, जो उसके 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशन को एकीकृत करेगा। आयोग जल्द ही ईसीआईनेट नाम से एक सिंगल-प्लेटफॉर्म एप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा।

चुनाव आयोग ने रविवार को बताया कि ईसीआईनेट चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा। नए एप के विकसित होने से उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग एप डाउनलोड करने और उनके अलग-अलग लॉगइन याद रखने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ईसीआईनेट का डेवलपमेंट अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और इसकी कार्यक्षमता, उपयोग में सरलता और साइबर सुरक्षा को लेकर परीक्षण किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग इस एप को लॉन्च कर सकता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।

एप से जुड़ेंगे 10.5 लाख बूथ लेवल अफसर

ईसीआईनेट वोटर हेल्पलाइन एप, वोटर टर्नआउट ऐप, सीविजिल, सुविधा, सक्षम और केवाई एप जैसे 40 से अधिक मौजूदा एप को एकीकृत करेगा। ईसीआईनेट से न केवल 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं को सुविधा होगी, बल्कि देशभर के 10.5 लाख बूथ लेवल अफसर, 15 लाख राजनीतिक एजेंट्स, 45 लाख से ज्यादा पोलिंग अधिकारी, 15,597 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 4,123 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर और 767 जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) भी इससे जुड़ेंगे।

सभी राज्यों से ली गई सलाह

चुनाव आयोग के इस नए एप को 36 राज्यों और केंद्र प्रदेश के सीईओ, 767 डीईओ और 4,123 ईआरओ की सलाह-मशविरे के बाद विकसित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आयोग ने इसके लिए 9,000 पेजों वाले 76 से ज्यादा दस्तावेजों, नियमों और दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है।

कानूनी दायरे में होगा ईसीआईनेट... *अधिकारियों ने बताया कि ईसीआईनेट एप के जरिये दी जाने वाली सभी सेवाएं और डाटा चुनाव आयोग की ओर से तय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, निर्वाचन नियम 1960, और चुनाव प्रक्रिया नियम 1961 के अंतर्गत ही संचालित होंगे।*

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की परिकल्पना है नया एप

चुनाव आयोग का कहना है कि यह एप मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की परिकल्पना है। उन्होंने इसे मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओज) के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

निर्वाचन आयोग ला रहा है 'ईसीआई-नेट'

नई दिल्ली।

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक सुलभ, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग एक नया वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म 'ईसीआई-नेट' विकसित कर रहा है, जो मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समेत सभी हितधारकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करेगा। यह नया प्लेटफॉर्म आयोग के मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब ऐप्स को एकीकृत करेगा, जिससे यूजर्स को बार-बार ऐप डाउनलोड करने, लॉगिन याद रखने और जटिल नेविगेशन से छुटकारा मिलेगा। ईसीआई-नेट का यूजर इंटरफेस (यूआई) सुंदर और सहज होगा तथा इसका यूजर एक्सपीरियंस बेहद सरल और प्रभावी रहेगा।

इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन में की गई थी, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी शामिल थे।

ईसीआई-नेट की विशेषताएं

- यह उपयोगकर्ताओं को डेस्कटॉप और स्मार्टफोन दोनों पर सुसंगत और अधिकृत चुनावी डेटा तक पहुंच प्रदान करेगा।
- केवल अधिकृत निर्वाचन अधिकारी ही इस पर डेटा दर्ज कर सकेंगे, जिससे इसकी सटीकता सुनिश्चित होगी।
- किसी विवाद की स्थिति में केवल सांविधिक फॉर्मों में दर्ज प्राथमिक डेटा को ही मान्य माना जाएगा।

ईसीआई-नेट में शामिल होने वाले लोकप्रिय ऐप्स में वोटर हेल्पलाइन, सी-विजिल, सुविधा 2.0, सक्षम, ईएसएमएस और केवाईसी ऐप जैसे प्लेटफॉर्म होंगे, जिन्हें मिलाकर 5.5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। यह प्लेटफॉर्म देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं और पूरे चुनावी तंत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, जिसमें 10.5 लाख से अधिक बीएलओ, 15 लाख बीएलए, 45 लाख चुनाव अधिकारी, 15,597 एईआरओ, 4,123 ईआरओ और 767 जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हैं। ईसीआई-नेट का विकास अंतिम चरण में है। इसे विकसित करते समय 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सीईओ, सभी डीईओ और ईआरओ से परामर्श लिया गया है। साथ ही आयोग द्वारा जारी चुनावी नियमों व पुस्तिकाओं की भी गहन समीक्षा की गई है।

ईसीआई-नेट से जुड़े सभी डेटा और सेवाएं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 तथा चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत स्थापित कानूनी ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगी। यह डिजिटल पहल भारतीय चुनाव प्रणाली को भविष्य के लिए और अधिक सशक्त व विश्वसनीय बनाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग जल्द लॉन्च करेगा हितधारकों के लिए एकल-बिंदु ऐप

नई दिल्ली। एक प्रमुख पहल के तहत, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचकों और इनके अन्य हितधारकों जैसे चुनाव पदधारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफेस विकसित कर रहा है। यह नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल बनाएगा। ईसीआई-नेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस (यूआई) और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस (यूएक्स) होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की थी। ईसीआई-नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में भी सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। संबंधित पदधारी द्वारा की गई प्रविष्टि से यह सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉर्मों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा। ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है (ऐप्स की पूरी सूची संलग्न है)। ईसीआई-नेट से लगभग 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के 10.5 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 15 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), लगभग 45 लाख मतदान पदधारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ), 4,123 ईआरओ और 767 ज़िला चुनाव अधिकारी (डीईओ) शामिल हैं। ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुका है और इसकी सुचारू कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करके एक विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ-साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है। ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़े लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग जल्द लॉन्च करेगा हितधारकों के लिए एकल-बिंदु ऐप

इबादत न्यूज

नई दिल्ली, 4 मई। एक प्रमुख पहल के तहत, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचकों और इनके अन्य हितधारकों जैसे चुनाव पदधारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफेस विकसित कर रहा है। यह नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल बनाएगा।

ईसीआई-नेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस (यूआई) और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस (यूएक्स) होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।

इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की थी।

ईसीआई-नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में भी सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। संबंधित पदधारी द्वारा की गई प्रविष्टि से यह सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉर्मों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा।

ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है (ऐप्स की पूरी सूची संलग्न है)। ईसीआई-नेट से लगभग 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के 10.5 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 15 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), लगभग 45 लाख मतदान पदधारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(एईआरओ), 4,123 ईआरओ और 767 ज़िला चुनाव अधिकारी (डीईओ) शामिल हैं।

ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुका है और इसकी सुचारू कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करके एक विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ-साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है।

ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़े लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।

सिरसा में नशा तस्कर

भारत निर्वाचन आयोग जल्द लॉन्च करेगा हितधारकों के लिए एकल-बिंदु ऐप

सीमा किरण

नई दिल्ली। एक प्रमुख पहल के तहत, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचकों और इनके अन्य हितधारकों जैसे चुनाव पदधारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफेस विकसित कर रहा है। यह नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल बनाएगा।

ईसीआई-नेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस (यूआई) और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस (यूएक्स) होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की थी। ईसीआई-नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में भी सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। संबंधित पदधारी द्वारा की गई प्रविष्टि से यह सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉर्मों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा। ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है (ऐप्स की पूरी सूची संलग्न है)। ईसीआई-नेट से लगभग 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के 10.5 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 15 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), लगभग 45 लाख मतदान पदधारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ), 4,123 ईआरओ और 767 ज़िला चुनाव अधिकारी (डीईओ) शामिल हैं।

ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुका है और इसकी सुचारू कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करके एक विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ-साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है।

ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़े लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।

आ ... ली।
तीन ... गुरु
को ... विंद
ने प ... ा।

दै.न.ज्यो
05-05-2025

निर्वाचन आयोग जारी करेगा नया ऐप

एजेंसी/नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज की सुविधा और कार्यप्रणाली को सरल बनाने के लिए जल्द ही वन स्टॉप प्लेटफार्म के रूप में ईसीआई नेट नेट नाम की ऐप शुरू करने जा रहा है जो मौजूदा 40 मोबाइल ऐप का काम करेगी। निर्वाचन आयोग ने रविवार को कहा कि वह एक नया उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल इंटरफेस विकसित कर रहा है। यह ऐप सभी चुनाव-संबंधित गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। यह कदम उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।

मौजूदा 40 से अधिक आईटी ऐप्स को इस उन्नत यूआई यूएक्स वाले ऐप में शामिल किया जाएगा

भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही हितधारकों के लिए एक एकल-बिंदु ऐप लॉन्च करेगा

दिल्ली / सवाईमाधोपुर , 4 मई। एक प्रमुख पहल के तहत, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचकों और इनके अन्य हितधारकों जैसे चुनाव पदधारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस विकसित कर रहा है। यह नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल बनाएगा।

ईसीआई-नेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस (यूआई) और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस (यूएक्स) होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।

इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की थी।

ईसीआई-नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफ़ोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में भी सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। संबंधित पदधारी द्वारा की गई प्रविष्टि से यह सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉर्मो में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा।

ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है (ऐप्स की पूरी सूची संलग्न है)। ईसीआई-नेट से लगभग 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के 10.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 15 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), लगभग 45 लाख मतदान पदधारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ), 4,123 ईआरओ और 767 ज़िला चुनाव अधिकारी (डीईओ) शामिल हैं।

ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुका है और इसकी सुचारू कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करके एक विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ-साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है। ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकडे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग जल्द लॉन्च करेगा हितधारकों के लिए एकल-बिंदु ऐप

नई दिल्ली। एक प्रमुख पहल के तहत, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचकों और इनके अन्य हितधारकों जैसे चुनाव पदधारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफेस विकसित कर रहा है। यह नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल बनाएगा। ईसीआई-नेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस (यूआई) और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस (यूएक्स) होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।

इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की थी।

ईसीआई -नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में भी सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। संबंधित पदधारी द्वारा की गई प्रविष्टि से यह सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉर्मों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा।

ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है (ऐप्स की पूरी सूची संलग्न है)।

ईसीआई-नेट से लगभग 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के 10.5 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 15 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), लगभग 45 लाख मतदान पदधारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ), 4,123 ईआरओ और 767 ज़िला चुनाव अधिकारी (डीईओ) शामिल हैं।

ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुका है और इसकी सुचारू कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करके एक विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ-साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है।

ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़े लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग जल्द लॉन्च करेगा एकल-बिंदु ऐप

40 से अधिक आईटी ऐप्स को इस उन्नत यूआई/ यूएक्स वाले ऐप में शामिल किया जाएगा

दैनिक पर्यटन बाजार

जोधपुर। एक प्रमुख पहल के तहत, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचकों और इनके अन्य हितधारकों जैसे चुनाव पदधारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस विकसित कर रहा है। यह नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल (reorient) बनाएगा।

ईसीआई-नेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस (यूआई) और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस (यूएक्स) होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की थी।

ईसीआई-नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफ़ोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में भी सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। संबंधित पदधारी द्वारा की गई प्रविष्टि से यह सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉर्मों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा।

ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है (ऐप्स की पूरी सूची संलग्न है)। ईसीआई-नेट से लगभग 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है।

ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुका है और इसकी सुचारू कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करके एक विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ-साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है।

ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़े लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।

हुकमनामा समाचार

भारत निर्वाचन आयोग जल्द लॉन्च करेगा हितधारकों के लिए एकल-बिंदु ऐप

नई दिल्ली। एक प्रमुख पहल के तहत, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचकों और इनके अन्य हितधारकों जैसे चुनाव पदधारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफेस विकसित कर रहा है। यह नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल बनाएगा। ईसीआई-नेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस (यूआई) और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस (यूएक्स) होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।

इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की थी।

ईसीआई -नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में भी सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। संबंधित पदधारी द्वारा की गई प्रविष्टि से यह सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉर्मों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा।

ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है (ऐप्स की पूरी सूची संलग्न है)।

ईसीआई-नेट से लगभग 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के 10.5 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 15 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), लगभग 45 लाख मतदान पदधारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ), 4,123 ईआरओ और 767 जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) शामिल हैं।

ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुका है और इसकी सुचारू कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करके एक विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ-साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है।

ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़े लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।

40 से ज्यादा मौजूदा एप्स होंगे खत्म, 100 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को होगा फायदा

एक ही एप में मिलेंगी चुनाव से जुड़ी सभी सुविधाएं

नई दिल्ली(ए)। चुनाव आयोग ऑफ इंडिया अब देशभर के करोड़ों मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रहा है। आयोग जल्द ही ईसीआईनेट नाम से एक सिंगल-प्लेटफॉर्म एप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। यह एप चुनाव आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत कर देगा।

ईसीआईनेट एप को खासतौर पर बेहतर यूज़र इंटरफेस और सरल यूजर एक्सपीरियंस के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे मतदाता और अधिकारी बिना किसी झंझट के

चुनाव से जुड़ी हर जानकारी तक पहुंच सकें। अब बार-बार अलग-अलग एप्स डाउनलोड करने और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी। इस आधुनिक प्लेटफॉर्म की कल्पना मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ग्यानेश कुमार ने मार्च 2025 में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में की थी, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद थे।

ईसीआईनेट के जरिए उपयोगकर्ता अब अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से ही जरूरी चुनावी जानकारी तक पहुंच पाएंगे। खास बात यह है कि इस ऐप पर अपलोड की जाने वाली सभी जानकारियां केवल अधिकृत चुनाव अधिकारी ही दर्ज करेंगे, जिससे डेटा की सटीकता बनी रहेगी। हालांकि, किसी भी विवाद की स्थिति में स्टैच्युटरी फॉर्म्स में भरी गई जानकारी ही अंतिम मानी जाएगी।

इस नई पहल के तहत चुनाव आयोग के पॉपुलर एप्स को भी ईसीआईनेट में मर्ज कर देगा। इन एप्स को अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।

ईसीआईनेट से न केवल 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं को सुविधा होगी, बल्कि देशभर के 10.5 लाख शेष पृष्ठ 6 पर...

कानूनी दायरे में होगा ईसीआईनेट

ईसीआईनेट ऐप के जरिए दी जाने वाली सभी सेवाएं और डेटा चुनाव आयोग द्वारा तय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, निर्वाचन नियम 1960, और चुनाव प्रक्रिया नियम 1961 के अंतर्गत ही संचालित होंगे।

एक ही एप में मिलेंगी....

बूथ लेवल अफसर, 15 लाख राजनीतिक एजेंट्स, 45 लाख से ज्यादा पोलिंग अधिकारी, 15,597 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 4,123 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर और 767 जिला चुनाव अधिकारी भी इससे जुड़ेंगे। ईसीआईनेट का डेवलपमेंट अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और इसकी कार्यक्षमता, उपयोग में सरलता और साइबर सुरक्षा को लेकर कड़े ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इसे 36 राज्यों/टीएस के सीईओ, 767 डीईओ और 4,123 ईआरओ की सलाह–मशविरे के बाद विकसित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आयोग ने इसके लिए 9,000 पेजों वाले 76 से ज्यादा दस्तावेजों, नियमों और गाइडलाइंस की समीक्षा की है।

दैनिक
स्मार्ट मरुधर

आजाद भारत की बुलन्द आवाज

वर्ष-04 अंक-77 पृष्ठ-4 जयपुर, राजस्थान सोमवार, 5 मई, 2025 RNI N

चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम

अब ईसीआई एप पर होंगी चुनाव से जुड़ी सभी सुविधाएं

मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए किया अहम बदलाव

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

चुनाव आयोग ऑफ इंडिया अब देशभर के करोड़ों मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव कर रहा है। आयोग जल्द ही ईसीआईनेट नाम से एक सिंगल-प्लेटफॉर्म एप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। यह एप चुनाव आयोग की 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत कर देगा। एप को खासतौर पर बेहतर यूजर इंटरफेस और सरल यूजर एक्सपीरियंस के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे मतदाता और अधिकारी बिना किसी झंझट के चुनाव से जुड़ी हर जानकारी तक पहुंच सकें। अब अलग-अलग एप्स डाउनलोड करने और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी।

40 से ज्यादा मौजूदा एप्स को खत्म

- इसकी कल्पना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की
- यह भी स्पष्ट किया स्टैच्युटरी फॉर्म्स में भरी गई जानकारी ही अंतिम मानी जाएगी

मोबाइल या डेस्कटॉप पर मिलेगी पूरी जानकारी

इस आधुनिक प्लेटफॉर्म की कल्पना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मार्च में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में की थी, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद थे। नेट के जरिए उपयोगकर्ता अब अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से ही जरूरी चुनावी जानकारी तक पहुंच पाएंगे। खास बात यह है कि इस एप पर अपलोड की जाने वाली सभी जानकारियां केवल अधिकृत चुनाव अधिकारी ही दर्ज करेंगे, जिससे डेटा की सटीकता बनी रहेगी। हालांकि विवाद की स्थिति में स्टैच्युटरी फॉर्म्स में भरी गई जानकारी ही अंतिम मानी जाएगी।

ये एप्स होंगे शामिल

इस नई पहल के तहत चुनाव आयोग वोटर हेल्पलाइन एप ,वोटरटर्नआउट एप, सी विजिल, सुविधा 2.0,ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी एप जैसे पॉपुलर एप्स को भी ईसीआई नेट में मर्ज कर देगा। इन एप्स को अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।

RNI NO. 53791/93

दैनिक विशेष गरिमा समाचार

पत्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, मेघालय, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा एवं केरल से पत्रकार जुड़े।

contact us:email:
visheshgarima@gmail.com
Mobile.9314017636, 8209073743

विशेष गरिमा

जयपुर व शिमला से एक साथ प्रसारित

आप अपने संस्थान के समाचार हमें दैनिक विशेष गरिमा,
VG NEWS
चैनल एवं पोर्टल
www.visheshgarima.page में प्रकाशन हेतु vishesh-garima @gmail.com
पर भेज सकते हैं।
वाट्सअप - 9314017636

वर्ष: 14 | अंक:298 | जयपुर, सोमवार, 5 मई 2025 | हिंदी दैनिक | पृष्ठ:4 | मूल्य: 1 रुपए

चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम

अब ईसीआई एप पर होंगी चुनाव से जुड़ी सभी सुविधाएं

मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए किया अहम बदलाव

एजेंसी/नई दिल्ली

चुनाव आयोग ऑफ इंडिया अब देशभर के करोड़ों मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव कर रहा है। आयोग जल्द ही ईसीआईनेट नाम से एक सिंगल-प्लेटफॉर्म एप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। यह एप चुनाव आयोग की 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत कर देगा। एप को खासतौर पर बेहतर यूजर इंटरफेस और सरल यूजर एक्सपीरियंस के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे मतदाता और अधिकारी बिना किसी झंझट के चुनाव से जुड़ी हर जानकारी तक पहुंच सकें। अब अलग-अलग एप्स डाउनलोड करने और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी।

40 से ज्यादा मौजूदा एप्स को खत्म

- इसकी कल्पना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की थी
- यह भी स्पष्ट किया स्टैच्युटरी फॉर्म्स में भरी गई जानकारी ही अंतिम मानी जाएगी

मोबाइल या डेस्कटॉप पर मिलेगी पूरी जानकारी

इस आधुनिक प्लेटफॉर्म की कल्पना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मार्च में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में की थी, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद थे। नेट के जरिए उपयोगकर्ता अब अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से ही जरूरी चुनावी जानकारी तक पहुंच पाएंगे। खास बात यह है कि इस एप पर अपलोड की जाने वाली सभी जानकारियां केवल अधिकृत चुनाव अधिकारी ही दर्ज करेंगे, जिससे डेटा की सटीकता बनी रहेगी। हालांकि, विवाद की स्थिति में स्टैच्युटरी फॉर्म्स में भरी गई जानकारी ही अंतिम मानी जाएगी।

ये एप्स होंगे शामिल

इस नई पहल के तहत चुनाव आयोग वोटर हेल्पलाइन एप, वोटरटर्नआउट एप, सी विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी एप जैसे पॉपुलर एप्स को भी ईसीआई नेट में मर्ज कर देगा। इन एप्स को अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।

100 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को होगा इससे फायदा

इस नेट से न केवल 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं को सुविधा होगी, बल्कि देशभर के 10.5 लाख बूथ लेवल अफसर, 15 लाख राजनीतिक एजेंट्स, 45 लाख से ज्यादा पोलिंग अधिकारी, 13,597 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 4,123 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर और 767 जिला चुनाव अधिकारी भी इससे जुड़ेंगे। इसका डेवलपमेंट अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और इसकी कार्यक्षमता, उपयोग में सरलता और साइबर सुरक्षा को लेकर कड़े ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इसे 36 राज्यों के सीईओ, 767 डीईओ और 4,123 ईआरओ की सलाह-मशविरे के बाद विकसित किया जा रहा है। आयोग ने इसके लिए 9,000 पेजों वाले 76 से ज्यादा दस्तावेजों, नियमों और गाइडलाइंस की समीक्षा की है।

यह पूरी तरह से कानूनी दायरे में होगा

ईसीआई नेट एप के जरिए दी जाने वाली सभी सेवाएं और डेटा चुनाव आयोग द्वारा तय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, निर्वाचन नियम 1960, और चुनाव प्रक्रिया नियम 1961 के अंतर्गत ही संचालित होंगे।

पोस्ट रजि. नम्बर: जोधपुर/507/2024-26

RNI REG. NO. : RAJHIN/2022/86076

दैनिक सच मीडिया

हमेशा सच के साथ...

आवश्यकता

समाचार, लेख, सूचना, आलेख, कविता, विज्ञापन व जिलेवार एजेंसी के लिये सम्पर्क करें-

सुमेर सिंह चुण्डावत

संपादक

मो. 7737275324

वर्ष 03 › अंक 134 दैनिक हिन्दी प्रातः कालीन | जोधपुर , सोमवार 05 मई 2025 | EMail: sachmedia0001@gmail.com | मूल्य: 2 रुपये › पृष्ठ : 08

चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम

अब ईसीआई एप पर होंगी चुनाव से जुड़ी सभी सुविधाएं

मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए किया अहम बदलाव

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

चुनाव आयोग ऑफ इंडिया अब देशभर के करोड़ों मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव कर रहा है। आयोग जल्द ही ईसीआईनेट नाम से एक सिंगल-प्लेटफॉर्म एप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। यह एप चुनाव आयोग की 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत कर देगा। एप को खासतौर पर बेहतर यूजर इंटरफेस और सरल यूजर एक्सपीरियंस के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे मतदाता और अधिकारी बिना किसी झंझट के चुनाव से जुड़ी हर जानकारी तक पहुंच सकें। अब अलग-अलग एप्स डाउनलोड करने और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी।

40 से ज्यादा मौजूदा एप्स को खत्म

- इसकी कल्पना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की थी
- यह भी स्पष्ट किया स्टैच्युटरी फॉर्म्स में भरी गई जानकारी ही अंतिम मानी जाएगी

मोबाइल या डेस्कटॉप पर मिलेगी पूरी जानकारी

इस आधुनिक प्लेटफॉर्म की कल्पना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मार्च में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में की थी, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद थे। नेट के जरिए उपयोगकर्ता अब अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से ही जरूरी चुनावी जानकारी तक पहुंच पाएंगे। खास बात यह है कि इस एप पर अपलोड की जाने वाली सभी जानकारियां केवल अधिकृत चुनाव अधिकारी ही दर्ज करेंगे, जिससे डेटा की सटीकता बनी रहेगी। हालांकि, विवाद की स्थिति में स्टैच्युटरी फॉर्म्स में भरी गई जानकारी ही अंतिम मानी जाएगी।

ये एप्स होंगे शामिल

इस नई पहल के तहत चुनाव आयोग वोटर हेल्पलाइन एप, वोटरटर्नआउट एप, सी विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी एप जैसे पॉपुलर एप्स को भी ईसीआई नेट में मर्ज कर देगा। इन एप्स को अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।

100 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को होगा इससे फायदा

इस नेट से न केवल 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं को सुविधा होगी, बल्कि देशभर के 10.5 लाख बूथ लेवल अफसर, 15 लाख राजनीतिक एजेंट्स, 45 लाख से ज्यादा पोलिंग अधिकारी, 15,597 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 4123 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर और 767 जिला चुनाव अधिकारी भी इससे जुड़ेंगे। इसका प्लेटफॉर्म अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और इसकी कार्यक्षमता, उपयोग में सरलता और साइबर सुरक्षा को लेकर कड़े टेस्ट किए जा रहे हैं। इसे 36 राज्यों के सीईओ, 767 डीईओ और 4123 ईआरओ की सलाह-मशविरे के बाद विकसित किया जा रहा है। आयोग ने इसके लिए 9,000 पेजों वाले 76 से ज्यादा दस्तावेजों, नियमों और गाइडलाइंस की समीक्षा की है।

यह पूरी तरह से कानूनी दायरे में होगा

ईसीआई नेट एप के जरिए दी जाने वाली सभी सेवाएं और डेटा चुनाव आयोग द्वारा तय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, निर्वाचन नियम 1960, और चुनाव संचालन नियम 1961 के अंतर्गत ही संचालित होंगी।